crease in their price. It is also proposed to develop an effective monitoring mechanism to strictly monitor the prices of drugs of decontrolled category with a view to bringing any of such drugs within the ambit of control, should it be considered necessary to do so.

Criteria for no-industry district

18. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI T. R. BALU:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have decided to modify the criteria to decide no industry area by changing the present definition of no-industry area; and

(b) if so, what are the details of the proposed new policy and by when it is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The existing Schemes of incentives for industrialisation of backward areas/ 'No Industry Districts' have been reviewed by an Inter-Ministerial Committee. Recommendations of the Committee are under the consideration of Government.

भारतीय विधिज्ञ परिषद

19. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री 9 मार्च, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1414 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् का यह नियम कि दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों को अंग्रेजी भाषा की प्रवीणता परीक्षा उतीर्ण करनी होती है--कब से लागू है । क्या ऐसा नियम "क" क्षेत्र में जिसे हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है, और कहीं लागू है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वज) : भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अंग्रेजी भाषा में लिखित परीक्षा में प्रवीणता से संबंधित नियम 1-8-1971 से प्रवृत्त हैं । यह नियम सम्पूर्ण भारत पर लागू है ।

पैट्रोल और गैस की खोज

20. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कहां-कहां पेट्रोल और गैस की खोज का कार्य चल रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान इन पर कितनी राशि खर्च की गयी और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है ;

(ख) सर्वेक्षण के आधार पर आकलित कितने स्थानों में तेल के पता लगने की संभावना है जहां खोज अथवा खुदाई का कार्य अभी शुरू किया जाना है ;

(ग) किन-किन स्थानों पर खोज के लिए स्वदेशी यंत्र इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और कितनी विदेशी कम्पनियों के यंत्र इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और उनके प्रभार क्या हैं ; और

(घ) कौन-कौन से देश इस कार्य में किन-किन स्थलो पर और किस प्रकार से सहयोग प्रदान कर रहे हैं और वह यह सहयोग कब से प्रदान कर रहे हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालयम में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विधि पुस्तकें

21. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री 9 मार्च, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित

प्रश्न 1413 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालयों में राजभाषा फार्मूला के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों की अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कानून की पुस्तकों और पत्रिकाओं पर निर्भर करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबध में क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी नहीं । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने, 1264 केन्द्रीय अधिनियमों के अद्यतन प्राधिकृत पाठ हिन्दी में प्रकाशित किए हैं । बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों को द्विभाषीय रूप (अंग्रेजी-हिन्दी) में भी प्रकाशित किया गया है । केन्द्रीय सरकार हिन्दी में दो विधि पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर रही है, जिनमें से एक उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और दूसरी उच्च न्यायालयों के निर्णयों को प्रकाशित करने के लिए है । इसके अतिरिक्त, हिन्दी में विधि पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष पारितोषिक देकर प्राइवेट प्रकाशकों को प्रोत्साहित करती है ।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों का प्रश्न है राज्य सरकारों को, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 137 और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अधीन न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को विनिर्दिष्ट करने के लिए शक्ति दी गई है । जहां तक हमें ज्ञात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकांश कार्य हिन्दी में किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश और बिहार के न्यायालयों में भी बड़ी मात्रा में कार्य हिन्दी में किया जा रहा है । हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने भी विधि न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ा दिया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों पर, राज्य के विधान को और राज्य उच्च न्यायालय के निर्णयों को हिन्दी में उपलब्ध कराने की आवश्यकता के महत्व के बारे में बल देती रहती है ।

न्यायालय के हिन्दी में निर्णय

22. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या विधि और न्याय मंत्री 9 मार्च, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1412 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अंग्रेजी से हिन्दी में बदलाव लाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, इस आशय का कोई संवैधानिक संशोधन लाने का विचार रखती है कि उच्चतम न्यायालय पुनरीक्षण के समय, हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में दिए गए निर्णयों पर विचार केवल हिन्दी भाषा में करें ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों को अपने न्यायालयों के निर्णय हिन्दी में दिए जाने का आग्रह करेगी; जैसा कि अन्य हिन्दी भाषी राज्यों में किया जा रहा है ; और

(ग) क्या "क" और "ख" क्षेत्रों के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय देश की राजभाषा पर लगे प्रतिबन्ध को, जो स्वतंत्र देश के लिए कलंक है, हटाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद से आग्रह करेगी ताकि अधिवक्ता अपना काम हिन्दी में भी कर सकें ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । संविधान के अनुच्छेद 348(2) और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन राज्य